SHRI ANNASAHEB M.K. PATDL : Sir, actually, we have given a lot of support for calamity relief in Gujarat. In fact, we have given almost Rs. 89.66 crores.

श्री सभापति : नहीं , आप तो यह बता दीजिए कि जिन स्टेट्स में मिनिमम वेजेज़ एक्ट लागू है उन स्टेट्स में जा कुछ आप सहायता दे रहे हैं , वहां मिनिमम वेजेज़ एक्ट के अनुसारमज़दूरों को पेमेंट किया जाए , क्या इस तरह के निर्देश दिए हैं ?

SHRI ANNASAHEB M.K. PAUL : Sir, actually, we have seen that no complaint has been received from anybody regarding the wages. But, somehow, it has been questioned here. We will certainly look into it.

श्री सभापति : एक मिनट , कंप्लेंट की आवश्यकता नहीं हैं ।

श्री सभापति : अब हो गया । ..... (व्यवधान)

श्री राजू परमार : निर्देश देना चाहिए । अभी वहां ....(व्यवधान)

श्री सभापति : मैनें सारा पूछ लिया । .....(व्यवधान)

श्री राजू परमार : पूरे गुजरात में अकाल की वजह से काफी स्केयरसिटी ....(व्यवधान)

श्री सभापति : आप सब की जगह मैंने पूछ लिया है । अब आप बैठिए ।....(व्यवधान)

श्री राजू परमार : अभी और काफी रिलीफ फंड ....(व्यवधान)

श्री सभापति : नैक्स्ट क्वश्चन ।

*462. [The Questioner (Shri Janardhana Poojaiy was absent. For answer *vide* pages 43—44 *infra.]*

Representation of Women in Police

*463. DR. ABRAR AHMED: ††
SHRI RAJEEV SHUKLA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state: (a) whether Centre has advised States to encourage more representation of women in police through various methods;

††The question was actually asked on the floor of the house by Dr. Abrar Ahmed.

(b) whether financial assistance is also provided for the purpose; and

(c) if so, the details thereof?

THEMMSTER OF STATEIN THEMINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI I.D. SW AMI): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir. These are part of the recommendations of the National Police Commission and the Padmanabhaiah Committee on Police Reforms set up by the Central Government which have been sent to the States for implementation.

(b) and (c) No, Sir.

डा. अबरार अहमद : जी , महिलाओं का मामला है । माननीय सभापति महोदय, पुलिस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के बारे में यह सवाल था । माननीय मंत्री जी ने यह लिखा है कि प्रधानभया समिति की सिफारिर्शो के अंग हैं जिन्हें कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों को भेज दिया गया है , लेकिन दिल्ली जो आपके अधीन है और केन्द्र शासित प्रदेश जो आपके अधीन आते हैं , उनके बारे में इस सिफारिश के कार्यान्वयन के बारे में आपने कुछ नहीं लिखा कि उसके बारे में आपको जो करना था वह आपने कुछ नहीं किया ? एक और चीज़ मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं ।

श्री सभापति : दोनों सप्लीमेंटरी एक साथ मत करिए ।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : चेयरमैन सर, इन फैक्ट सब स्टेट्स को भी और यूनियन टैरिटरीज़ को भी बार-बार इसके बारे में लिखा गया है और उसमें प्रोगैस भी हुई है । ऐसी बात नहीं है , सारे हिन्दुस्तान में आज 129 लेडीज़ आईपीएस आफिसर्ज़ हैं और जो हमारी सैन्ट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनमें भी एक बटालियन रेज़ की जा रही है । सीआरपीएफ ने आलरेडी दो विमेन बटालियन रेज़ की है । ये सारे एक्शन लिए गए हैं और उनको एन्करेज़ किया जा रहा है । जब हम मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस की बात करते है तब भी उनको यह कहा जाता है कि जो पैसा आपको आ रहा है वह इसमें आप यूज़ करे । हां , यह बात सही है कि कोई रिज़र्वेशन नहीं हैं ।

डा.अबरार अहमद : सभापति महोदय , 19से 21फरवरी , 2002 को दिल्ली में नेशनल कांफ्रेंस फॉर विमेन इन पुलिस का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें पुलिस में महिलाओं के रेक्रूटमेंट और रिप्रेजेटेशन को 33 परसेंट करने का अनुरोध किया गया था । क्या माननीय मंत्री जी यह सुनिश्चित करेंगे कि हर जिले में कम से कम एक महिला पुलिस थाना हो ताकि पुलिस थानों में महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न को समाप्त किया जा सकें ?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : सर, उस रेकमेंडेशन से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्ज़ एग्री नहीं करती कि रिज़र्वेशन के लिए कुछकहा जाए , इसलिए हमने स्टेट्स को नहीं भेजा हैं । जहां तक विमेन पुलिस स्टेशंज़ की बात है तो उसके लिएहमने सब को लिखा है । टोटल नंबर ऑफ विमेन पुलिस स्टेशंज़ इन द कंट्री आज 453 हैं । इसमें आन्ध्र प्रदेश ने लीड ली है । वहां 273 ऐसे पुलिस स्टेशन हैं । तमिलनाडु के 107 ऐसे पुलिस स्टेशन हैं और उन्होंने तो विमेन बटालियन रेज़ करने का भी प्रोपोज़ल बनाया है । तो सभी स्टेट्स ने ....(व्यवधान)

श्री सभापति : ठहरिए –ठहरिए, बोलने दीजिए। ....(व्यवधान) बोलने दीजिए ।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : हम इसको एन्करेज करते हैं , स्टेट्स को एडवाइस भेजते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे पुलिस स्टेशन आप बनाइये और जितनी रेकमेंडेशंज हैं , चाहे पुलिस कमीशन की आई हैं, चाहे पद्दानाभैय्या कमेटी की आई हैं , वे सब स्टेट्स को भेजी हैं । स्टेट्स को बार-बार कहा जाता है, बल्कि एनुअल काफ्रेंस में डीजीज़ चीफ सेक्रेटरीज़ और चीफ मिनिस्टर्ज़ कांफ्रेस में भी अन्य इश्यूज़ के साथ-साथ यह इश्यू भी लिया जाता हैं ।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : 1 won't allow you. Now, Shri Rajeev- Shukla.

श्री राजीव शुक्ल : मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 473 विमेन पुलिस स्टेशन हैं और उनको बढ़ाने की योजना है लेकिन, दूसरे जवाब में बोलते हैं कि स्टेट्स को कोई फाइनांशेल असिस्टेंस देने का प्रावधान नहीं है और न ही दिए जाने की कोई योजना है । राज्यों की जो हालत है, जो वित्तीय स्थिति हैं, उसमें विमेन पुलिस स्टेशंज के लिए और विमेन का रिप्रेज़ेटेंशन बढ़ाने के लिए अगर वित्तीय सहायता एलोकेट नहीं करेंगे .....। इसलिए मुझे नहीं लगता कि राज्य सरकारें इसे कर पाएंगी । मैं जानना चाहूंगा कि मंत्री जी का इस मामले में क्या कहना है ?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : सर, सेंट्रल गवर्नमेंट , मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस के लिए बहुत पैसा देती है और उस पैसे में यह भी हैं कि नए पुलिस स्टेशन बनाना, वूमेन पुलिस को टॉयलेट फेसिलिटी देना , उनके लिए सेपरेट रेस्ट देना आदि । यह कम्पोनेंट्स मॉडर्नाइज़ेशन की स्कीम में आते हैं और इनके लिए सभी स्टेट्स को पैसा दिया जाता हैं । उसी पैसे से ये काम करने हैं । हां , यह बात सही है कि हम वूमेन पुलिस में रिक्रूटमेंट करने के लिए कोई सेपरेट पैसा लेकिन सफीसिएंट पैसा पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए दिया जाता हैं ।

श्री सभापति : प्रश्न संख्या -464. श्रीमती प्रेमा करियप्पा – अनुपस्थित ।

श्री मोती लाल वोरा : मान्यवर , मैं रक्षा मंत्री जी से संबंधित प्रश्न नहीं पूछना चाहता ।

श्री सुरेश पचौरी : महोदय, माननीय रक्षा मंत्री जी जिन्हें हम रक्षा मंत्री मानने के लिए तैयार नहीं हैं , चाइना गए हैं । चाइना में "सार्स" फैला हुआ है और जब वह वापिस आएं तो कहीं " सार्स " लेकर न आएं । इसके लिए मेडिकल जांच एअरपोर्ट पर ही होनी बहुत जरूरी हैं । उन्हें ऐसे समय में तो चाईना जाना ही नहीं था ....(व्यवधान).... यह तो राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न हैं ।

*464. [The Questioner (Shrimati Prema Cariappa) was absent For answer *vide* pages 44—45 *infra]*

*465. [The Questioner (Shri Yadlapati Venkat Rao) was absent For answer *vide* page 45 *infra]*

Core Groups on Reforms

*466. SHRI R.P. GOENKA: Will the Minister of PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS bepleased to state:

(a) whether it is a fact that two separate Core Groups on Administrative Reforms and social sector have been set up recently to suggest changes in administrative systems and procedures to speed up the pace of reforms and various policies being implemented by different Ministries to achieve the objectives of the Tenth Five Year Plan; and

(b) if so, the details thereof, including the personnel of the Core Groups, their specific agenda and time-frame fixed for making their recommendations?